



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 908 ]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 1, 2003/आश्विन 9, 1925

No. 908 ]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2003/ASVINA 9, 1925

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2003

संदर्भ : गृह मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. का.आ. 603 (अ)।

का.आ. 1149(अ).— यतः अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को गृह मंत्रालय की उक्त अधिसूचना के तहत 17-9-1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में उक्त जिले इस प्रकार की अशांत एवं खतरनाक स्थिति में थे कि सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक था; और

2. यतः माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दर्ज किए गए बयान में भारत सरकार ने बताया था कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किए जाने संबंधी सभी विद्यमान अधिसूचनाओं की 20-8-1997 से तीन माह की अवधि के भीतर समीक्षा की जाएगी;

3. स्थिति की पिछली बार मार्च, 2003 में समीक्षा की गई थी और दिनांक 31-3-2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 365(अ) के तहत तीरप एवं चांगलांग की 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषणा की अवधि को 30-9-2003 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। तीरप और चांगलांग जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की पुनः समीक्षा की गई है। अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों में विद्रोह की स्थिति बनी हुई है। विद्रोही संगठन सुरक्षा बलों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाइयों का सहारा लेने के अतिरिक्त बड़े पैमाने पर जबरन धन-वसूली में लगे हुए हैं। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चलाए जा रहे विद्रोह विरोधी अभियान तथा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से सुधार हुआ है। केन्द्र सरकार यह महसूस करती है कि इन प्रयासों को न केवल जारी रखने की बल्कि इनमें तेजी लाने की भी आवश्यकता है;

4. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर केन्द्र सरकार की यह राय है कि तीरप और चांगलांग जिलों में स्थिति अशांत है और कि ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं कि वहाँ सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती को जारी रखा जाना चाहिए। अतः यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की उपर्युक्त अधिसूचना 31 मार्च, 2004 तक लागू रहेगी बशर्ते कि इसे पहले वापस न लिया जाए।

[फा. सं. 13/27/99-एम.जेड.]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव (एन ई)

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2003

Ref : Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 603(E) dated 17-9-1991.

S.O. 1149(E).— Whereas Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 *vide* this Ministry's Notification referred to above, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid to civil power was necessary; and

2. Whereas in a statement filed before the Hon'ble Supreme Court, the Government of India had stated that all current notifications regarding declaration of 'disturbed areas' under the aforesaid Act, would be reviewed within a period of three months from 20-8-1997;

3. The situation was last reviewed in March 2003 and *vide* Notification bearing S.O. 365(E) dated 31-3-2003, it was decided to extend the tenure of the declaration of Tirap and Changlang as 'disturbed areas' upto 30-9-2003, a further review of the law and order situation in Tirap and Changlang districts has since been undertaken. These two districts of Arunachal Pradesh continue to be in the grip of insurgency. The insurgent outfits have been indulging in large-scale extortion besides resorting to acts of violence directed against the security forces. The sustained counter-insurgency operation by the Security Forces and steps taken by the State Government has shown improvement. The Central Government feels that these efforts not only need to be sustained but intensified;

4. In the light of the above, the Central Government is of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exist for the use of armed forces in aid of civil power. It has, therefore, been decided that the notification dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 31st March, 2004 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-MZ]

RAJIV AGARWAL, Jt. Secy. (NE)